2782 करोड़ की लागत से संवरेंगी प्रदेश की सड़कें

आगरा एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ औद्योगिक क्षेत्र की तलाशी जा रही संभावनाएं : मुख्य सचिव

लखनऊ (एसएनबी) । प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, लखनऊ- आगरा एक्सप्रेस-वे को मात्र आवागमन सड़क के रूप में न कर सड़क के दोनों और वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास को और अधिक गति देने के लिए पर्यटन, ऊर्जा, परिवहन सेक्टर सहित अन्य विभागों में भी परियोजनाएं तैयार कराकर भारत सरकार की स्वीकृति मिलने के उपरान्त एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए विचार किया जा रहा है। मुख्य सचिव गुरुवार को होटल ताज में एशियन विकास बैंक द्वारा आयोजित एक दिवसीय ओरिएन्टेशन प्रोग्राम के अवसर पर सम्बोधित कर रहे थे।

एशियन विकास बैंक द्वारा आयोजित एक दिवसीय ओरिएन्टेशन प्रोग्राम का शुभारंभ

उन्होंने कहा कि प्रदेश को निर्णयार्थ प्रस्तुत करने के पूर्व समस्त विभागों द्वारा यह प्रयास किये जायें कि परियोजना से आच्छदित भौगोलिक क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तथ्यों का समावेश हो। कार्यशाला में एडीबी के कन्ट्री डायरेक्टर केनिची योकोयामा तथा अन्य प्रतिनिधियों द्वारा एशियन विकास बैंक के क्रिया- कलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया गया कि वर्तमान में एशियन विकास बैंक द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के वित्त- पोषण के साथ-साथ परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में प्रदेश भर में एडीबी के सहयोग से ऊर्जा, परिवहन, शहरी विकास वित्त कृषि एवं मानव विकास से सम्बन्धित 84 परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं व उत्तर प्रदेश में ₹ 2782.00 करोड़ की लागत से लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मुख्य जिला सड़क विकास परियोजना को संचालित किया जाना है, जिसका एमओयू हस्ताक्षरित किया जा चुका है। एशियन बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा कार्यक्र में अवगत कराया गया कि वर्तमान में एशियन विकास

बैंक द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के वित्त- पोषण के साथ- साथ परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। कार्यशाला में एशियन विकास बैंक के कन्ट्री डायरेक्टर सहित नियोजन, अवस्थापना, एंव औद्योगिक विकास, ग्राम्य विकास, पर्यटन, कृषि, वित्त, ऊर्जा, नगर विकास, परिवहन, लोक निर्माण विभाग, परती भूमि विकास, वन, सिचाई तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने प्रतिभाग किया।